JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका का अध्ययन :–

KUMOD KUMAR

सारांशः–

मौद्रिक नीति एक व्यापक आर्थिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्त्ति को घटाने या बढ़ाने के लिए करता है ताकि अर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके साथ ही देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक उपकरणों का उपयोग बाजार में ऋण की उपलब्धता को विनियमित करने और आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिया किया जाता है ।

Key Words:- मौद्रिक नीति, रेपोरेट, साख नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक, परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि इत्यादि ।

प्रस्तावनाः–मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति का एक मुख्य हिस्सा है, यह नीति केन्द्रीय बैंक की ओर से बनाई जाती है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के साख का नियंत्रण एवं नियमन तथा आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना होता है । मौद्रिक नीति के जरिए ब्याज दरों, धन की आपूर्त्ति और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाता है।

उद्देश्यः–

मौद्रिक नीति के कुछ मुख्य उद्देश्य है–

(क) अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करना ।

(ख) मूल्य स्थिरता बनाए रखना ।

(ग) रोजगार सृजित करना ।

(घ) विनिमय दर को स्थिर करना ।

मौद्रिक नीति के प्रकारः–

मौद्रिक नीति को मुख्य रूप से दो वर्गो में विभाजित किया जाता है।

(क) विस्तारवादी मौद्रिक नीति (ख) संकुचित मौद्रिक नीति

(क) विस्तारवादी मौद्रिक नीतिः–

इसका प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्त्ति को बढ़ाना होता है। इसे निम्न तरीकों से लागू किया जा सकता है ।

(1) ब्याज दरों में कमी –इससे उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाता है।

(2) बैको के लिए नकद रिजर्व अनुपात (CRR) कम करना –

इससे वाणिजियक बैंकों के पास अपने ग्राहको को उधार देने के लिए अधिक धन शेष बचता है जिससे अर्थव्यवस्था में अधिक धन का संचरण होता है।

(3) केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की नकद खरीद RBI भुगतान करके अर्थव्यस्था में से सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करता है जिसके कारण बाजार में वित्तीय प्रवाह बढ़ जाता है।

विस्तारवादी मौद्रिक नीति का लक्ष्य व्यवसायिक बैंकों और उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना होता है। हालांकि कभी–कभी इससे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति की Hyper inflation स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

(4) संकुतिच मौद्रिक नीति :–

इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है । इसे निम्न तरीकों से लागू किया जाता है।

(क) ब्याज दरों में वृद्धि–इससे उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाता है।

(ख) बैंको के लिए CRR बढ़ाना–इससे बैंको के पास अपने ग्राहको को उधार देने के लिए कम धन शेष बचता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है।

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय –सरकारी प्रतिभूतियों के खरीददार RBI को नकद भुगतान करते हैं जिससे बाजार में उपलब्ध धन कम हो जाता है।

इस प्रकार संकुचित मौद्रिक नीति का लक्ष्य मुद्रास्फीति को कम करना होता है।

भारत में मौद्रिक नीति –

भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा RBI को देश के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में वर्ष 2016 में एक बड़ा परिवर्तन किया गया । 2016 से पहले, भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने का दायित्व सिर्फ RBI गवर्नर के पास था । 2016 के बाद, वित्तीय अधिनियम 2016 ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना के लिए Act 1934 में संशोधन किया । वर्तमान मौद्रिक नीति, द्वारा तैयार की जाती है।

भारत में मौद्रिक नीति और केन्द्र सरकार के बीच एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

तद्नुसार, RBI Act 1934 में संशोधन किया गया और भारत में मौद्रिक नीति एवं मुद्रास्फीति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया गया ।

भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC – मौद्रिक नीति समिति की स्थापना RBI द्वारा गठित उर्जित पटेल समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था । संशोधित RBI Act 1934 की घारा 452B एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC का प्रावधान करती है ।

MPC में कुछ प्रमुख प्रावधान :–

(क) समिति की वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होती है ।

(ख) समिति में 6 सदस्य होगें ।

(ग) MPC के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगें ।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना :–

(क) RBI गवर्नर अध्यक्ष ।

(ख) मौद्रिक नीति के प्रभारी RBI के डिप्टी गवर्नर ।

(ग) RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी ।

(घ) 3 सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

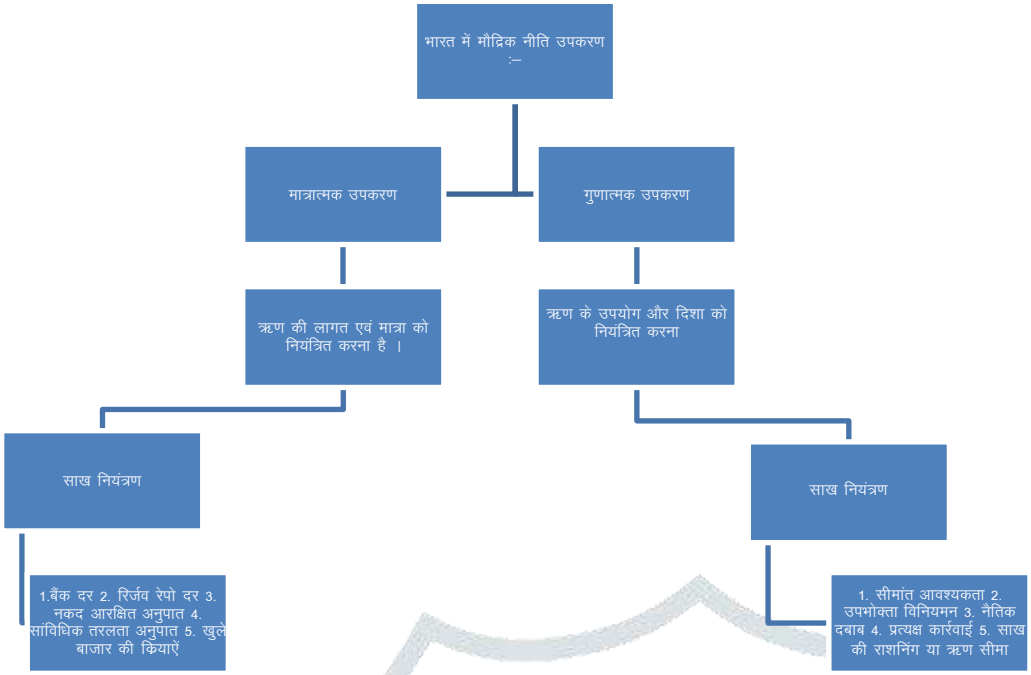

मौद्रिक नीति का महत्त्वः–

1. इस नीति द्वारा मूल्य स्थिरता बनाए रखने एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है।
2. मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है ।
3. इस नीति के द्वारा उपभोग, बचत, निवेश और पूंजी–निर्माण जैसे चरों को प्रबंधित किया जाता है।
4. इस नीति द्वारा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मुद्रा विनिमय दरों को संतुलित किया जाता है।
5. इस नीति से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित कर अधिक रोजगार सृजित किए जाते हैं ।

भारत में मौद्रिक नीति की सीमाऐं :–

1. बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अभाव
2. मुद्रा बाजार
3. काला धन
4. विरोधाभाषी उद्देश्य
5. मुद्रा प्रणाली की सीमाऐं

निष्कर्ष :–

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और सतत विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संदर्भ :–

(i) www.rbi.nic.in

(ii) www.diristiias.com

(iii) www.pib.nic.in

(iv) www.ncert.com